न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया के समक्ष

प्रोग्रेसिव पॉली प्लास्ट कंपनी (पी) लिमिटेड,-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी।

1984 की सिविल रिट याचिका संख्या 2736।

31 जनवरी 1985.

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार-बॉम्बे में सहायक कलेक्टर द्वारा पारित मूल्यांकन का अनंतिम आदेश-चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई आदेश-जिस माल के संबंध में शुल्क लगाया गया था उसे चंडीगढ़ में वितरित किया जाना था-निष्पादित शुल्क के भुगतान के लिए ज़मानत बांड चंडीगढ़ में जहां निर्धारिती का पंजीकृत कार्यालय भी स्थित था - कार्रवाई का कारण या उसका कोई हिस्सा - क्या यह चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है - ऐसे न्यायालय - क्या याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है।

माना गया कि कार्रवाई के कारण का मतलब हर उस तथ्य से है जिसे वादी के लिए निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा। कार्रवाई के कारण का बचाव पक्ष से कोई संबंध नहीं है जो प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जा सकता है और न ही यह वादी द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह उस मीडिया को संदर्भित करता है जिस पर वादी न्यायालय से उसके पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है। याचिका में लगाया गया आदेश सहायक कलेक्टर सीमा शुल्क, बॉम्बे का अंतरिम मूल्यांकन आदेश है, और तथ्य यह है कि माल को बॉम्बे में डिलीवरी लेने के बाद चंडीगढ़ ले जाया जाना था; वह। शुल्क के भुगतान के लिए ज़मानत बांड चंडीगढ़ में निर्धारिती द्वारा निष्पादित किया गया था, कि चंडीगढ़ में स्थित निर्धारिती की संपत्ति डिफ़ॉल्ट के मामले में बेची जाने योग्य थी या फर्म का पंजीकृत कार्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। जहां तक विवादित आदेश की वैधता का सवाल है, कार्रवाई के कारण पर इसका कोई असर नहीं है। इनमें से कोई भी परिस्थिति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्रवाई के कारण का हिस्सा नहीं बनती है और इसलिए, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है।

(अनुच्छेद 10 और 11)

सीमा शुल्क अधिनियम (1962 का एलआईआई) - धारा 18 - मूल्यांकन का अनंतिम आदेश निर्धारिती को कोई दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बुलाए बिना पारित किया गया - ऐसा आदेश - चाहे इस आधार पर अमान्य हो के अनुसार सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश। - 'एस.1.1' बी.'-क्या यह कहा जा सकता है कि इसे किसी बाहरी प्राधिकारी के निर्देश पर पारित किया गया है।

माना गया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(1) के खंड (सी) के अवलोकन से पता चलता है कि यह स्पष्ट शब्दों में किसी भी दस्तावेज या जानकारी के उत्पादन, अन्य बातों के अलावा, अनंतिम आदेश पारित करने का प्रावधान करता है। किसी आयातक या निर्यातक के पास इसका अधिकार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, अनुभाग का खंड (सी)। अधिनियम की धारा 18 में केवल अंतिम आदेश पारित करने के उद्देश्य से सभी दस्तावेजों और पूरी जानकारी के उत्पादन और किसी भी परीक्षण या पूछताछ को पूरा करने की परिकल्पना की गई है, न कि अनंतिम आदेश पारित करने के उद्देश्य से और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनंतिम आदेश ख़राब है क्योंकि इसे निर्धारिती से अपेक्षित दस्तावेज़ या पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहे बिना पारित किया गया था।

(अनुच्छेद 8)

माना गया कि अभिव्यक्ति 'एस.आई.आई.बी. के अनुसार' है। आदेश' का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि आदेश 'एस.आई.आई.बी.' के आदेश के तहत पारित किया गया था। अभिव्यक्ति 'एस.आई.आई.बी.' का अर्थ विशेष खुफिया जांच ब्यूरो है, एक संगठन जिसका कार्य जांच करना और वास्तविक कीमतों का निर्धारण करना है। आयातित सामान। यह असामान्य नहीं है कि आयातक कम बिलिंग में शामिल होते हैं और इसलिए, उक्त संगठन उन देशों में वस्तुओं की मौजूदा कीमतों के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करता है जहां से इन्हें आयात किया जाता है, और इस तरह की जानकारी सीमा शुल्क कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। आवश्यकता पड़ने पर, वह आयातित वस्तुओं के सही मूल्य का आकलन करने में सक्षम हो सके। 'एस.आई.आई.बी.' द्वारा प्रदान की गई ऐसी जानकारी पर अस्थायी रूप से आधारित सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर की कार्रवाई को अवैध नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपने कार्यों और अधिकारों को 'एस.आई.आई.बी.' को सौंप दिया है।

(अनुच्छेद 9)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह (उनके साथ डी.एस. वालिया एडवोकेट)। •

प्रतिवादी की ओर से जी.एस. चावला, अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया

(1) मोशन बेंच का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीशों ने 1984 की रिट याचिका संख्या 2736, 2791 और 4606 को स्वीकार करने के सवाल पर एक-दूसरे से असहमति जताई और प्रारंभिक आपत्ति से संबंधित विस्तृत विचार-विमर्श राय लिखी। न्यायालय के क्षेत्राधिकार और आक्षेपित आदेश की वैधता के संबंध में। इस तरह ये रिट याचिकाएँ मोशन सुनवाई के लिए मेरे सामने सूचीबद्ध हुईं।

(2) जहां दो सुविचारित विचार हो सकते हैं, मामला विस्तृत विचार के लिए स्वीकार किए जाने योग्य है। अत: प्रकरण स्वीकार किये जाते हैं।

(3) चूँकि दोनों पक्षों के वकील के पास अपनी अलग-अलग राय में दोनों न्यायाधीशों द्वारा नोटिस की गई बातों के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए वे एक सामान्य प्रश्न के रूप में याचिकाओं के निपटान के लिए सहमत हो गए। इन सभी मामलों में कानून शामिल है। जहां भी तथ्यों का संदर्भ आवश्यक हो, उन्हें 1984 की सिविल रिट संख्या 2736 से लिया जा सकता है।

4) याचिकाकर्ता भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय चंडीगढ़ में है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स डियोगियास कंपनी लिमिटेड बैंकॉक (थाईलैंड) ने अपने संपर्क अधिकारी/इंडेंटर मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के माध्यम से 500 मीट्रिक टन ऐक्रेलिक प्लास्टिक स्क्रैप की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता-कंपनी के साथ एक अनुबंध किया। कुचला हुआ) यूएस $240 प्रति मीट्रिक टन की दर से,—रिट याचिका के अनुलग्नक पी1 और पी2 के अनुसार; पिंजौर (जिला अंबाला) के मेसर्स खन्ना एंटरप्राइजेज ने ऐक्रेलिक प्लास्टिक स्क्रैप (कुचल) के आयात के लिए सक्षम प्राधिकारी से दो आयात लाइसेंस प्राप्त किए, - आयात लाइसेंस, अनुलग्नक पी.3 और पी.4 के माध्यम से; कि उक्त मेसर्स खन्ना एंटरप्राइजेज ने याचिकाकर्ता-कंपनी को दो प्राधिकरण पत्रों, अनुलग्नकों पी 5 और पी 6 के माध्यम से उपर्युक्त वस्तु को आयात करने के उद्देश्य से अपना एजेंट नियुक्त किया; कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक, चंडीगढ़ के साथ यू.एस. $61,3i90 के लिए एक अपरिवर्तनीय दस्तावेजी क्रेडिट खोला, क्रेडिट पत्र के अनुसार, अनुलग्नक पी7 और पी8 की प्रतियां; और वह 69 एम.टी. की खेप। याचिकाकर्ता-कंपनी के लिए ऐक्रेलिक प्लास्टिक स्क्रैप (कुचला हुआ) 19 अप्रैल, 1984 को शिपमेंट द्वारा, इंडेंट, अनुलग्नक पी 4 और पी 2 के अनुसरण में, उक्त दस्तावेजों में उल्लिखित कीमत और भाग्य पर भेजा गया था, अर्थात। यूएस $ 240 प्रति मीट्रिक टन। यह भी आरोप लगाया गया है कि सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे, प्रतिवादी नंबर 2 ने कस्टम-ड्यूटी लगाने के प्रयोजनों के लिए चालान में उल्लिखित मूल्य

को स्वीकार करने के बजाय, मनमाने ढंग से और याचिकाकर्ता-कंपनी को नोटिस दिए बिना मूल मूल्य की गणना की। प्रति मीट्रिक टन 475 अमेरिकी डॉलर की दर पर वस्तु और विवादित आदेश, अनुबंध पी.10 के माध्यम से उक्त बढ़े हुए मूल्य पर सीमा शुल्क लगाया गया, और कहा गया, - उक्त आदेश के तहत, रुपये का भुगतान करने के लिए। कस्टम ड्यूटी के माध्यम से 4,25,281 अधिक। उन्होंने याचिकाकर्ता-कंपनी को नकद रुपये जमा करने का आदेश दिया। सीमा शुल्क के 20 प्रतिशत के कारण 85,056/32 और शेष राशि के लिए याचिकाकर्ता-कंपनी को एक बांड निष्पादित करने की आवश्यकता थी, अनुलग्नक पी 11। याचिकाकर्ता-कंपनी को इस प्रकार सीमा शुल्क का 20 प्रतिशत का भुगतान करना था और भारी विलंब शुल्क के भुगतान से बचने के लिए बांड निष्पादित करें। याचिकाकर्ता-कंपनी ने कस्टम कलेक्टर की कार्रवाई को इसी स्तर पर चुनौती दी है, क्योंकि उसे डर है कि बाद की खेपों पर भी इसी तरह से कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है।

5) मोशन बेंच के समक्ष याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर उत्तरदाताओं की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति थी। यह दावा किया गया था कि इस मामले में अकेले बॉम्बे हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र था, कि सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर ने एक अनंतिम आदेश पारित किया था और इसलिए, रिट याचिका समय से पहले थी, और किसी भी मामले में याचिकाकर्ता-कंपनी को अपना अधिकार समाप्त कर लेना चाहिए था। आक्षेपित अनंतिम आदेश के विरुद्ध क़ानून के अंतर्गत उपाय।

(6) जैसा कि न्यायाधीशों की असहमतिपूर्ण राय से स्पष्ट है, जिन्होंने पहली बार मोशन सुनवाई के समय मामले की सुनवाई की थी, याचिकाकर्ता-कंपनी ने सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर के आदेश को दो आधारों पर चुनौती दी थी (1) कि विवादित आदेश याचिकाकर्ता-कंपनी को कोई दस्तावेज़ या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बुलाए बिना पारित किया गया था, और (2) सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर द्वारा एक बाहरी प्राधिकारी के निर्देश पर और इसलिए, की नज़र में पारित किया गया था। कानून के अनुसार, आक्षेपित आदेश को उक्त अधिकारी का आदेश नहीं माना जा सकता।

7) क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति के संबंध में न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह ने निम्नलिखित शब्दों में विचार व्यक्त किया:

"यह सवाल कि क्या इस न्यायालय के पास रिट याचिकाओं पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है या नहीं, बहस के दौरान विचार के लिए सामने आया और पहले ही देखा जा चुका था, इस संबंध में उत्तरदाताओं की ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाता है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 का कार्यालय, जिसके मूल्यांकन के आदेश को इन रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है, बॉम्बे में स्थित है। विद्वान वकील ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है कि न्यायालय के पास याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है:

(a) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) में प्रावधान है कि किसी भी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग संबंधित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। वे क्षेत्र जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण की सीट या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर नहीं है।

(b) विद्वान वकील के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियाँ इस तथ्य की सूचक हैं कि कार्रवाई का कारण आंशिक रूप से, यदि पूरी तरह से नहीं, तो चंडीगढ़ में उत्पन्न हुआ है, जो इस न्यायालय की सीट है और यह तथ्य होगा याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करें:
(i) याचिकाकर्ता-फर्म का पंजीकृत कार्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। यह तथ्य इंडेंट, अनुलग्नक पीएल और पी 2 में उल्लिखित पते से भी स्पष्ट है, जो निर्यातक फर्म द्वारा ऐक्रेलिक प्लास्टिक स्क्रैप की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया था; -

(ii) कि अपरिवर्तनीय दस्तावेजी क्रेडिट याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, चंडीगढ़ के माध्यम से देय था, जैसा कि अनुबंध पी.7 और पी.8 द्वारा प्रमाणित है;
(iii) प्रवेश बिल, अनुलग्नक पी.14 और पी.15 में, जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया है, याचिकाकर्ता-कंपनी का नाम जिसका कार्यालय चंडीगढ़ में है, आयातकों के रूप में और संबंधित कॉलम में उल्लिखित है। वस्तु के गंतव्य स्टेशन का उल्लेख 'चंडीगढ़ वाया बॉम्बे' के रूप में किया गया है;
(iv) याचिकाकर्ता-कंपनी की ओर से निष्पादित बांड अनुबंध पी.एल.एल. पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 17, चंडीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया था;
(v) डिफ़ॉल्ट के मामले में कस्टम ड्यूटी याचिकाकर्ता या चंडीगढ़ में उनके बैंकरों से वसूली योग्य थी, जो दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 12 या उसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अधिकारियों द्वारा पारित किसी भी आदेश का प्रभाव चंडीगढ़ में याचिकाकर्ता पर पड़ेगा।

(c) विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने अपने तर्क के समर्थन में कई अधिकारियों के अनुपात पर भरोसा किया है कि इस न्यायालय के पास वर्तमान याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। विशेष रूप से, उन्होंने एल. वी. वीरी चेट्टियार और अन्य बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, बॉम्बे एआईआर 1971 मद्रास 15 का हवाला दिया है जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

"कार्रवाई का कारण" को हमेशा कानूनी कार्यवाही में तथ्यों के बंडल के संदर्भ में समझा जाता है, और यदि तथ्यों के उस बंडल का एक भाग एक विशेष स्थान पर उपलब्ध है, देखा या देखा जा सकता है जो उच्च न्यायालय की सीट है, तो ऐसे उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 (1-ए) के बावजूद प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति है तथ्य यह है कि वह प्राधिकारी जिसके विरुद्ध अंतिम नियम जारी किया जाना है और जिसके कार्य ने संपूर्ण या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण बनाया है, उसकी क्षेत्रीय सीमा से बाहर स्थित है। व्यक्ति मुख्य रूप से प्रतिवादी द्वारा समय-समय पर याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने और उन्हें तमिलनाडु राज्य में किए गए अपने व्यवसाय के खातों को पेश करने के लिए कहने और फिर से अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उनका आकलन करने का प्रस्ताव देने से प्रभावित होता है। कुछ न्यायिक तथ्यों की धारणा, इस तरह के नोटिस का पता है और ऐसा स्नेह संबंधित मामले या कार्यवाही की समग्रता में तथ्यों के बंडल से संबंधित है, और ऐसा प्रभाव आवश्यक रूप से कार्रवाई के कारण को जन्म देता है, हालांकि यह आंशिक रूप से हो सकता है।"

याचिकाकर्ता के वकील ने हमारा ध्यान भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड और अन्य एसएलपी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया। (सिविल) 84 में से 3746 पर 27 मार्च 1984 को निर्णय हुआ:
'इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लुधियाना में है और मुख्य प्रतिवादी जिनके खिलाफ प्राथमिक राहत मांगी गई है, नई दिल्ली में हैं, किसी को उम्मीद होगी कि रिट याचिका पंजाब उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी और हरियाणा या दिल्ली हाई कोर्ट में.'
उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त केवल सर्वोच्च न्यायालय का एक आज्ञापालक है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्चतम न्यायालय का एक आज्ञापालन भी उच्च न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
7) विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अगला अधिकार दामोमल कौसोमल रायसिंगानी बनाम भारत संघ और अन्य एआईआर 1967 बॉम्बे 355 है डिवीजन बेंच ने इस मामले में कहा कि यह मानते हुए भी कि विवादित आदेश प्रतिवादियों द्वारा नई दिल्ली में दिया गया था, उस आदेश का प्रभाव याचिकाकर्ता पर वह स्थान गिरा जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था।

8) इसी प्रकार यूनाइटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (III), यू.पी. और अन्य, यह माना गया कि जहां यूपी सरकार। एक औद्योगिक विवाद को उत्तर प्रदेश में संदर्भित करने का आदेश पारित किया गया - औद्योगिक न्यायाधिकरण और ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन

कलकत्ता में रहने वाले एक पक्ष को दिया गया था, और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के परिणाम उस पर पड़ेंगे। कलकत्ता में पार्टी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास यूपी-सरकार को रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र था। एक अन्य मामले में सेराजुद्दीन एंड कंपनी बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य एआईआर 1971 कैल 411 में यह दोहराया गया था कि जिस उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ था, उसके पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने वेडसंस स्टील्स एंड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉम्बे और अन्य सीडब्ल्यू 2273/82 मामले में की गई टिप्पणियों को पूरा करते हुए 24 दिसंबर, 1982 को फैसला सुनाया एक डिवीजन बेंच द्वारा. इस न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग-अलग था क्योंकि, जैसा कि उस निर्णय में देखा गया था, माल की डिलीवरी बॉम्बे में की जानी थी और लॉग प्रविष्टि भी बॉम्बे में रद्द कर दी गई थी। वर्तमान मामले में यह तर्क दिया गया है कि खेप को चंडीगढ़ में वितरित किया जाना था, हालांकि माल को बॉम्बे के माध्यम से शिपमेंट द्वारा आना था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यह कानून का इरादा नहीं हो सकता है कि सीमा शुल्क विभाग और पूरे देश में फैले आयातकों के बीच सीमा शुल्क के भुगतान के संबंध में कोई भी विवाद केवल बॉम्बे उच्च न्यायालय में उठाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति गोयल ने अपनी भिन्न राय में उक्त प्रारंभिक आपत्ति के संबंध में निम्नलिखित शब्दों में विपरीत दृष्टिकोण रखा:
"जिस स्पष्ट दोष से याचिका ग्रस्त है वह इस याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी है जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा शुल्क के उप कलेक्टर द्वारा पारित अनंतिम मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ है। हालाँकि, याचिका में यह दिखाने के लिए कोई आधार नहीं बताया गया था कि इस न्यायालय के पास बॉम्बे में डिप्टी कलेक्टर द्वारा स्वीकार किए गए आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र कैसे है, फिर भी बहस के समय, यह आग्रह किया गया था कि एक भाग अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के कारण, इस न्यायालय के पास इस याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है, निम्नलिखित तथ्यों पर भरोसा रखा गया था:
(i) कि अनंतिम मूल्यांकन का आदेश याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ में दिया गया था;
(ii) जिस माल पर सीमा शुल्क लगाया गया है उसे चंडीगढ़ में वितरित किया जाना था;
(iii) अंततः मूल्यांकन किए गए शुल्क के भुगतान के लिए ज़मानत बांड चंडीगढ़ में याचिकाकर्ता द्वारा मूल्यांकन प्राधिकारी के पक्ष में निष्पादित किया गया था;
(iv) कि डिफ़ॉल्ट के मामले में बेची जाने वाली याचिकाकर्ता की संपत्ति चंडीगढ़ में स्थित है; और
(v) कि याचिकाकर्ता-कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सेक्टर 17, चंडीगढ़ में स्थित है।

पहली परिस्थिति तथ्यात्मक रूप से ग़लत है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने आयातित माल की डिलीवरी और सीमा शुल्क निकासी के लिए मेसर्स तुलसी दास खेम जी को अपना एजेंट नियुक्त किया। माल की डिलीवरी बंबई में उनके एजेंटों द्वारा की गई थी, और अनंतिम मूल्यांकन आदेश भी उनकी उपस्थिति में पारित किया गया था। इस प्रकार आदेश बॉम्बे में याचिकाकर्ता-कंपनी के एजेंटों को दिया गया, जो इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि याचिका के साथ प्रस्तुत आदेश की प्रति पर फर्म के कुछ सदस्य, मेसर्स तुलसी दास खेम जी, निजी, के हस्ताक्षर हैं। सीमित। इसलिए, यह आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है कि याचिकाकर्ता-कंपनी को चंडीगढ़ में विवादित आदेश दिया गया था। भले ही यह अन्यथा हो, फिर भी इसका कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश उसी क्षण लागू हो जाता है जब इसकी घोषणा की जाती है और ऐसा प्राधिकारी होता है प्रभावित व्यक्ति को आदेश संप्रेषित करने की कोई बाध्यता नहीं है।

10) शेष चार परिस्थितियों में से कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्रवाई के कारण का हिस्सा नहीं बनती है। कार्रवाई का कारण, जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने मोहम्मद खलील खान और अन्य बनाम महबूब अली मियां और अन्य एआईआर 1949 पी.सी. 78 में रखा था। इसका अर्थ है हर वह तथ्य जो वादी के लिए निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा। कार्रवाई के कारण का बचाव पक्ष से कोई संबंध नहीं है जो प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जा सकता है और न ही यह वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है। यह उस मीडिया को संदर्भित करता है जिस पर वादी न्यायालय से उसके पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है। इस आधिकारिक घोषणा के आलोक में, अब यह जांच की जानी चाहिए कि वे कौन से तथ्य हैं जो वर्तमान मामले में कार्रवाई का कारण बनते हैं।

11) जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ता डिप्टी, कलेक्टर, सीमा शुल्क के अंतरिम मूल्यांकन आदेश को रद्द करने के लिए इस न्यायालय में आया है। जैसा कि याचिका में कहा गया है, तथ्य यह है कि डिप्टी कलेक्टर ने आयातित वस्तुओं के मूल्य का मनमाने ढंग से मूल्यांकन किया है; डिप्टी कलेक्टर ने अपनी राय नहीं बनाई है और इसके बजाय विशेष खुफिया जांच ब्यूरो (एस.आई.आई.बी.) के कुछ आदेश पर भरोसा किया है और यह कि लागू आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जैसा कि पहले हुआ था कई बार कुछ वस्तुओं को संभवतः $240 प्रति मीट्रिक टन की कीमत पर तेल साफ़ किया गया। इन आधारों को बनाने वाले किसी भी तथ्य का इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई मूल नहीं है और इस प्रकार कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा संभवतः उक्त क्षेत्र के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ है। तथ्य यह है कि माल को बम्बई में डिलीवरी लेने के बाद चंडीगढ़ ले जाया जाना था; कि शुल्क के भुगतान के लिए ज़मानत बांड याचिकाकर्ता द्वारा चंडीगढ़ में निष्पादित किया गया था; याचिकाकर्ता की चंडीगढ़ स्थित संपत्ति डिफॉल्ट की स्थिति में बेची जा सकती है या फर्म का पंजीकृत कार्यालय चंडीगढ़ में स्थित है, इसका कार्रवाई के कारण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां तक कि आदेश की वैधता है। उपजिलाधिकारी चिंतित हैं। मेरे लिए इस मामले पर और अधिक विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से (मैसर्स वेडसंस स्टील एंड वायर्स (पी.) लिमिटेड बनाम बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बी एंड एमबे) मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के दायरे में आता है। और अन्य) (सुप्रा), जिसमें बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने की मांग की गई थी और याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि इस न्यायालय के पास इस पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में जिस निर्णय पर भरोसा किया, उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

12) सबसे महत्वपूर्ण निर्भरता एल. वी. वीरी चेट्टियार और अन्य बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, बॉम्बे, एआईआर 1971 मैड मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर रखी गई थी। 155, जिसमें बॉम्बे में कार्यरत बॉम्बे सेल्स टैक्स अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिस को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ विचार किया गया था:

'कार्रवाई का कारण' तथ्यों का समूह है जो किसी पक्ष को कानूनी कार्यवाही बनाए रखने में सक्षम बनाता है। कर लगाने वाले प्राधिकारी के नोटिस और उसके मूल्यांकन के प्रस्ताव के कारण प्राप्तकर्ता पर प्रभाव उस बंडल से संबंधित है और इस प्रकार कर लगाने वाले प्राधिकारी के खिलाफ रिट जारी करने के लिए कार्रवाई का कारण बनता है। इसलिए, एक रिट याचिका प्राप्तकर्ता के स्थान के उच्च न्यायालय में होगी, भले ही प्राधिकारी उस उच्च न्यायालय के बाहर स्थित हो क्षेत्रीय सीमाएँ।'

विद्वान न्यायाधीशों का अत्यंत सम्मान करते हुए, मैं इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हूं। प्राप्तकर्ता को नोटिस की तामील कार्रवाई के कारण या मूल्यांकन के प्रस्ताव का कोई हिस्सा नहीं बनती है। जैसे ही बिक्री कर अधिनियम के तहत अधिकारियों ने नोटिस जारी किया, यह सक्रिय और प्रभावी हो गया। यदि विद्वान न्यायाधीशों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही होगा, तो नोटिस की सेवा से बचने की स्थिति में और यह एक समाचार पत्र में उद्धरण के माध्यम से होगा, जहां भी प्राप्तकर्ता ने उस नोटिस को पढ़ा होगा, कार्रवाई का कारण उत्पन्न होगा। इसके अलावा, ऊपर देखे गए प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार, केवल वे तथ्य ही कार्रवाई का कारण बनते हैं जो वादी के लिए अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने के लिए आरोप लगाने और साबित करने के लिए आवश्यक हैं। स्पष्ट रूप से इसे चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी न किसी स्थान पर नोटिस की सेवा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक नोटिस में निहित मूल्यांकन के प्रस्ताव का सवाल है, यह उस स्थान पर अस्तित्व में आया जहां नोटिस तैयार किया गया था और जारी किया गया था। इसलिए, किसी भी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई का कारण उस स्थान पर उत्पन्न होता है जहां बिक्री कर के मूल्यांकन का प्रस्ताव नोटिस दिया जाता है। वर्तमान मामले के अलावा, इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर का अनंतिम आदेश याचिकाकर्ता के एजेंटों की उपस्थिति में पारित किया गया और इसकी प्रति उन्हें बॉम्बे में दी गई। इस लिहाज से भी यह मामला याचिकाकर्ता के लिए कोई मददगार नहीं है।

13) संयुक्त प्रांत इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और अन्य बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण (द्वितीय) इलाहाबाद और अन्य 79 कलकत्ता साप्ताहिक नोट्स 312 में, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई थी और याचिका पर इस आधार पर विचार किया गया था कि कलकत्ता में याचिकाकर्ताओं को पुरस्कार और वसूली के लिए नोटिस दोनों दिए गए।

विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, मैं फिर से ऊपर दर्ज किए गए कारणों से इस विचार पर सहमत होने में असमर्थता व्यक्त करता हूं। जहां तक पुरस्कार को चुनौती देने का सवाल है, पुरस्कार की तामील और वसूली के लिए नोटिस संभवतः कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा नहीं बन सकते। यह पुरस्कार इसकी सेवा से नहीं, बल्कि उस तिथि से प्रभावी होता है जिस दिन इसे बनाया गया था या यदि प्रकाशित होना आवश्यक हो, तो इसके प्रकाशन की तिथि से। पुरस्कार को चुनौती देने के लिए वसूली की सूचना को भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह केवल उन मामलों में होता है जहां कोई आदेश केवल संबंधित व्यक्ति पर उसकी तामील से प्रभावी होता है, ऐसा कहा जा सकता है कि आदेश की तामील उस स्थान पर कार्रवाई के कारण के एक हिस्से को जन्म देती है जहां आदेश तामील किया जाता है। जहां तक न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेशों का सवाल है, वे पारित होने के साथ ही प्रभावी हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित व्यक्ति पर लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां तक उन आदेशों को चुनौती देने का सवाल है, उन आदेशों का दोबारा क्रियान्वयन कार्रवाई के कारण का घटक नहीं होगा। सेराजुद्दीन एंड कंपनी बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (सुप्रा) और यूनाइटेड प्रोविंस इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (आईएलटी) उत्तर प्रदेश और अन्य, 1974 लैब में निर्णय। मामलों में 902 समान आधार पर आगे बढ़ते हैं और मुझे उन्हीं कारणों से उनका पालन करने में असमर्थता पर खेद है। ये सभी मामले वर्तमान मामले पर भी लागू नहीं होंगे क्योंकि यहां याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ में किसी भी समय कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

14) भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड और अन्य) (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी भरोसा किया गया था:
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लुधियाना में है और मुख्य प्रतिवादी जिनके खिलाफ प्राथमिक राहत मांगी गई है वे नई दिल्ली में हैं, किसी को उम्मीद होगी कि रिट याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। या दिल्ली उच्च न्यायालय में।'

उपरोक्त टिप्पणियाँ कलकत्ता की अदालत में दायर की गई याचिका को खारिज करते समय की गईं। उपर्युक्त टिप्पणियों में कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं की गई है कि याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विचारणीय होगी क्योंकि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लुधियाना में था। वादी या याचिकाकर्ता के निवास को किसी भी तर्क द्वारा कार्रवाई के कारण का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है और न ही वादी या याचिकाकर्ता का निवास उस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र दे सकता है जहां वह रहता है। इसलिए, उपरोक्त टिप्पणियों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जिस न्यायालय में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है, उसके पास उक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए, मेरी सुविचारित राय है कि इस न्यायालय के पास इस याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसे केवल इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है।"

सम्मान के साथ, मैं न्यायमूर्ति गोयल के विचार से पूरी तरह सहमत हूं और मानता हूं कि इस न्यायालय के पास इस याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

15) जहां तक सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर की विवादित कार्रवाई की योग्यता का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा जिन आधारों पर कार्रवाई को चुनौती दी गई है, उनमें से कोई भी उसके लिए उपयोगी नहीं है। पहले आधार की खूबियों का आकलन करने के लिए, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना सबसे पहले आवश्यक होगा, जो निम्नलिखित शर्तों में हैं:

“18. शुल्क का अनंतिम मूल्यांकन - (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी लेकिन धारा 46 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-
(सी) जहां आयातक या निर्यातक ने शुल्क के मूल्यांकन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और पूरी जानकारी प्रदान की है, लेकिन उचित अधिकारी शुल्क का आकलन करने के लिए आगे की जांच करना आवश्यक समझता है;
उचित अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे दस्तावेजों के प्रस्तुत होने या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसे परीक्षण या पूछताछ के पूरा होने तक ऐसे सामानों पर लगाए जाने वाले शुल्क का अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है यदि आयातक या निर्यातक, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करता है ऐसी सुरक्षा, जिसे उचित अधिकारी अंतिम रूप से मूल्यांकन किए गए शुल्क और अनंतिम रूप से मूल्यांकन किए गए शुल्क के बीच, यदि कोई हो, कमी के भुगतान के लिए उपयुक्त समझे।"
खंड (सी) के अवलोकन से पता चलता है कि यह स्पष्ट शब्दों में किसी आयातक या निर्यातक के कब्जे में मौजूद किसी भी दस्तावेज़ या जानकारी के उत्पादन, अन्य बातों के अलावा, अनंतिम आदेश पारित करने का प्रावधान करता है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 18 का एक खंड (सी) सभी दस्तावेजों और पूरी जानकारी के उत्पादन और किसी भी परीक्षण या पूछताछ को केवल अंतिम आदेश पारित करने के उद्देश्य से पूरा करने की परिकल्पना करता है, न कि अंतिम आदेश पारित करने के उद्देश्य से। अनंतिम आदेश और, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अनंतिम आदेश खराब है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता-कंपनी को आवश्यक दस्तावेज या पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए पहले बुलाए बिना पारित किया गया था। हालाँकि, यह जोड़ा जा सकता है कि प्रश्न में अनंतिम आदेश पारित करने से पहले, याचिकाकर्ता-कंपनी के एजेंट, जो डिलीवरी लेने के लिए अधिकृत थे, को विधिवत सुना गया था।

16) जहां तक दूसरे आधार का संबंध है कि विवादित आदेश किसी बाहरी प्राधिकारी के निर्देश पर पारित किया गया था, यह देखा जा सकता है कि यह दावा एस.आई.आई.बी. के अनुसार अभिव्यक्ति की गलत धारणा पर आधारित है। आदेश' परिशिष्ट पी.10 में घटित होता है। याचिकाकर्ता-कंपनी की ओर से उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ यह निकालने की मांग की गई है कि विवादित आदेश 'एस.आई.आई.बी.' के आदेश

के तहत पारित किया गया था। अभिव्यक्ति 'एस.आई.आई.बी.' 'विशेष खुफिया जांच ब्यूरो' के लिए खड़ा है - एक संगठन जिसका कार्य जांच करना है आयातित वस्तुओं की वास्तविक कीमतें निर्धारित करें। यह असामान्य नहीं है कि आयातक कम बिलिंग में लिप्त होते हैं और इसलिए, उक्त संगठन उन देशों में वस्तुओं की मौजूदा कीमतों के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करता है जहां से इन्हें आयात किया जाता है और सीमा शुल्क कलेक्टर को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है। जब भी आवश्यक हो, उसे आयातित वस्तुओं के सही मूल्य का आकलन करने में सक्षम बनाना। 'एस.आई.आई.बी.' द्वारा प्रदान की गई ऐसी जानकारी के आधार पर सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर की कार्रवाई को अवैध नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपने कार्यों और अधिकारों को 'एस.आई.आई.बी.' को सौंप दिया है। इसलिए, मेरा मानना है कि सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर का विवादित आदेश पूरी तरह से कानूनी है और कानून के अनुसार पारित किया गया है।

(17) ऊपर बताए गए कारणों से, ये तीन रिट याचिकाएं इस आधार पर खारिज की जानी चाहिए कि इस न्यायालय के पास उन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और इस आधार पर भी कि विवादित आदेश किसी भी कानूनी कमजोरी से ग्रस्त नहीं है। मैं तदनुसार ऑर्डर करता हूं। याचिकाकर्ता-कंपनी रुपये का भुगतान करेगी। प्रत्येक याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 को लागत के रूप में 500 रु.

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वहअपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा